शब्दबाणों का प्रहार

राष्ट्रबाण

मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय अखबार

संपादक : संजय बघेल

सिवनी

बुधवार 25 फरवरी 2026 | E-PAPER: www.rashtrabaan.in | वर्ष : 10 | अंक : 298 | पृष्ठ : 06 | मूल्य : 5.00 रुपए | www.facebook.com/rashtrabaan | www.twitter.com/rashtrabaan

न्यूज ब्रीफ

आसनसोल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल आया

आसनसोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल कोर्ट में मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे आधिकारिक ईमेल पर बम होने की धमकी मिली। जानकारी मिलते ही, पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोर्ट परिसर में छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना कि मामला शरारत का लग रहा है। आगे की जांच चल रही है।

कर्नाटक में स्कूल के बाहर 16 साल के छात्र की हत्या

शिवमोग्गा। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सुलैबैलु में एक सरकारी स्कूल के बाहर 16 साल के छात्र संकेथ की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना के सिलसिले में पुलिस ने 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, संकेथ क्लास में शामिल होने के बाद स्कूल के बाहर कुछ लड़कों के बीच चल रही बहस में बीच-बचाव करने गया था। बहस क्रिकेट मैच को लेकर थी। आरोप है कि इस दौरान लड़कों ने उसे छाती के पास हाथ से मारा गया, जिससे वह मौके पर गिर पड़ा।

भुवनेश्वर के सुपरमार्केट में 12 घंटे से आग लगी

भुवनेश्वर। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित लिंगिपुर इलाके के एक सुपरमार्केट में पिछले 12 घंटे से भयानक आग लगी है। सुपरमार्केट में सोमवार रात को आग लगी थी। मंगलवार दोपहर को सुपरमार्केट की बिल्डिंग के ऊपर के वीडियो सामने आए, जिसमें आग की लपटें धधकती हुई दिखीं। दमकल के अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

दिल्ली में स्कूल कैंपस के गार्ड रूम में आग लगी, वॉचमैन की मौत

नईदिल्ली। दिल्ली के रणहोला इलाके में मंगलवार सुबह एमसीडी प्राइमरी स्कूल के गार्ड रूम में आग लगने से वॉचमैन नरेश कुमार (58) की मौत हुई। वह दिल्ली नगर निगम में काम करता थे। 2027 में रिटायर होने वाले थे।

राष्ट्रबाण

अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका लोकप्रिय अखबार राष्ट्रबाण तो आज ही अपने हॉकर से बोलिए या हमे कॉल कीजिए

सिर्फ 100 रुपए महीना

संपर्क : 7000427433

केरल का नाम अब 'केरलम'

कैबिनेट की मंजूरी :सेवातीर्थ में पहली मीटिंग; रेल-मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ मंजूर

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी | rashtrabaan.in

पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में तीन रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं।

बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने तीन नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया-चांडिल और पुनारख-किऊल के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है।

पहले 2 राज्यों का नाम बदला था: उत्तरांचल बना उत्तराखंड: 2007 में केंद्र सरकार ने उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड करने के लिए एक बिल संसद में पारित किया। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हस्ताक्षर होते ही राज्य का नाम बदल गया।

उड़ीसा बना ओडिशा: 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उड़ीसा को ओडिशा नाम में बदले जाने के बिल को मंजूरी दी थी।

प्रस्ताव केरल विधानसभा को भेजा जाएगा

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति 'केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026' को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा की राय के लिए भेजेंगे। विधानसभा की राय मिलने के बाद, सरकार संसद में बिल पेश करेगी। संसद से पास होने पर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम हो जाएगा। केरल विधानसभा से 24 जून 2024 को प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का असल में मलयाली भाषा में नाम केरलम है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान, भाषा, संस्कृति और विकास को बढ़ावा देना है।

13 फरवरी को पीएम सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ

कैबिनेट की पिछली बैठक 13 फरवरी को पीएम के साउथ ब्लॉक वाले ऑफिस में हुई थी। इसके बाद पीएम को नए ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का ऑफिस 1947 से साउथ ब्लॉक में रहा। ये इमारत करीब 78 सालों से देश की सत्ता का केंद्र रही है। सेवा तीर्थ कॉम्पलेक्स में कुल 3 इमारतें हैं- सेवा तीर्थ-1, सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3। सेवा तीर्थ-1 में पीएम है। सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ-3 में ह्यस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। ये सभी ऑफिस पहले अलग-अलग जगहों पर थे।

मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की: राहुल

पीएम पर एपस्टीन-अडाणी के केस का दबाव, भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल

राष्ट्रबाण | भोपाल | एजेंसी | rashtrabaan.in

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एपस्टीन और अडाणी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया।

राहुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल ने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था।

राहुल ने कहा- मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया।

मोदी ने किसानों के साथ छल किया: खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी हैं। उन्होंने देश को बेच दिया। किसानों के साथ छल किया। मोदीजी रोज उठकर चाय पर बात करते थे, तो क्या देश को बेचने की बात करते थे। मोदीजी कांग्रेस शासन में पैदा हुए, उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए।

खड़गे के भाषण की बड़ी बातें: प्रधानमंत्री को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए- अगर नाम बदलना ही राजनीति है तो प्रधानमंत्री को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनका जन्म कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। उन्होंने मनरेगा समेत कई योजनाओं के नाम बदलने पर सवाल उठाए।

मोदी ट्रम्प के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते- प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाते और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दबाव में फैसले लेते हैं।

राहुल गांधी के भाषण की 5 बड़ी बातें

- मोदी ने बिना कैबिनेट से पूछे अमेरिका से डील की- प्रधानमंत्री ने लोकसभा से निकलते ही ट्रंप को फोन किया और बिना कैबिनेट से सलाह लिए डील के लिए तैयार होने की बात कह दी।
- किसानों और देश के हित से समझौता किया- सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में सोया, कपास और भुट्टा बेचने की छूट देने की तैयारी कर ली है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा।
- अमेरिका से ट्रेड डील दबाव में की गई - अमेरिका से ट्रेड डील दबाव और धमकी के कारण किया गया। एपस्टीन फाइल और अडाणी से जुड़े मामलों की वजह से सरकार झुकी।
- भारत को कुछ नहीं मिला, उल्टा नुकसान होगा - इस डील से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और हर साल अमेरिका से भारी मात्रा में सामान खरीदना पड़ेगा।
- देश की इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर पर खतरा - अगर अमेरिका से कपास और अन्य सामान सस्ते में आएंगे, तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्थानीय उद्योग कमजोर हो जाएंगे।

शंकराचार्य को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट में याचिका लगाई

बोले- प्रयागराज में आईपीएस अजय पाल साजिश रच रहे, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ

राष्ट्रबाण | वाराणसी | एजेंसी | rashtrabaan.in

बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है।

वहीं, 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी। कल यानी सोमवार को पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची। स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य और उनके करीबियों की जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक, प्रयागराज पुलिस आज शंकराचार्य से पूछताछ करने उनके आश्रम पहुंच सकती है। गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसी आशंका को देखते हुए शंकराचार्य ने वकील के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया है।

इधर, मंगलवार को शंकराचार्य

ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई। इसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं।

शंकराचार्य ने कहा- इनका नाम अजय पाल शर्मा है। इस समय इनके अधीन ही जांच चल रही है। एक हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिस का बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया।

भागवत बोले- आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सही

उन्होंने दो हजार सालों तक भेदभाव सहा, फिर भी देश के साथ गद्दारी नहीं की

राष्ट्रबाण | देहरादून | एजेंसी | rashtrabaan.in

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के एक हिस्से ने करीब दो हजार साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर दो सौ साल तक भी आरक्षण देना पड़े, तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।

आरएसएस प्रमुख सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित 'प्रमुखजन गोष्ठी' में पूर्व सैनिकों और अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे थे।

इस दौरान भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक हैं और उनकी रगों में एक ही खून बहता है।

सवाल जवाब में पढ़िए कार्यक्रम में क्या बोले भागवत...

सवाल: अग्निवीर योजना को लेकर उठ रही शंकाओं और सुधार की जरूरत पर आप क्या सोचते हैं?
जवाब: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व, उच्च सैन्य तैयारी और निरंतर प्रशिक्षण अनिवार्य हैं। अग्निवीर योजना एक प्रयोग है। अनुभवों के आधार पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकता हो तो सुधार एवं परिमार्जन पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि सेना की क्षमता, अनुशासन और दीर्घकालिक मजबूती बनी रहे।
सवाल: क्या राष्ट्र की शक्ति सीधे समाज की शक्ति पर निर्भर करती है?
जवाब: राष्ट्र के भाग्य निर्माण में समाज की केंद्रीय भूमिका होती है। समाज मजबूत और संगठित होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी सशक्त होगी। समाज का सामूहिक सामर्थ्य नागरिकों को बल देता है और नेतृत्व को प्रभावी बनाता है, इसलिए नेतृत्व का चरित्रवान और अनुशासित होना आवश्यक है।

अंडमान में समुद्र में हेलिकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग

तकनीकी खराबी आई; पवन हंस कंपनी के हेलिकॉप्टर में सवार सभी 7 लोग सुरक्षित

राष्ट्रबाण | श्री विजयापुरम | एजेंसी | rashtrabaan.in

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार सुबह 9.30 बजे एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। घटना के समय उसमें 5 यात्री और 2 पायलट सवार थे। इनमें 3 महिला, 3 पुरुष और एक बच्चा मौजूद थे।

अधिकारियों ने बताया कि पवन हंस कंपनी के हेलिकॉप्टर ने सुबह 8.30 बजे पोर्ट ब्लेयर से अंडमान के मायाबंदर के लिए

उड़ान भरी थी। हेलिकॉप्टर के मायाबंदर पहुंचने के पहले ही उसमें खराबी आ गई। इसके बाद रनवे से 300 मीटर पहले ही समुद्र में हेलिकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई। नागरिक उड्डयन निदेशक नितेश रावत ने बताया कि घटना में दोनों पायलट और 5 यात्री घायल हुए हैं। सभी को मायाबंदर के डॉ. राजेंद्र प्रसाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

केंद्र सरकार की हेलिकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस के प्रवक्ता ने बताया कि घटना के बाद पोर्ट ब्लेयर से राहत हेलिकॉप्टर भेजा गया था। मामले की जांच कराई जा रही है। एक दिन पहले ही झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत हुई थी।

एआई समिट हंगामा- उदय भानु 4 दिन हिरासत में

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। उन्हें आज सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया कि चिब ही घटना के मास्टरमाइंड हैं। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे।

लोकसभा अध्यक्ष ने 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए

हर ग्रुप में एक लीडर समेत 11 सांसद; फ्रांस में थरूर

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी | rashtrabaan.in

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को भारत और अन्य देशों के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए हैं। 18वीं लोकसभा के तहत गठित ग्रुप्स में सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हैं।

हर देश के लिए एक ग्रुप लीडर और 10 सदस्य हैं। भाजपा के सबसे ज्यादा 28 ग्रुप लीडर हैं।

कांग्रेस के 9, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तृणमूल कांग्रेस के 3-3 सांसद ग्रुप लीडर बनाए गए हैं।

ग्रुप लीडर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएफजी की जानकारी दी। उन्होंने 64 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप लीडर और बाकी सदस्यों की लिस्ट जारी की। रिजिजू ने पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने भारत और अन्य देशों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाने का प्रस्ताव दिया था।

पश्चिम बंगाल एसआईआर-ओडिशा-झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद

सुप्रीम कोर्ट बोला- इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए; 80 लाख दावों का निपटारा बाकी

राष्ट्रबाण | नईदिल्ली | एजेंसी | rashtrabaan.in

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया

में तेजी लाने के लिए झारखंड-ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को, पश्चिम बंगाल सरकार और श्वष्ट के बीच चल रही खींचतान से निराश होकर कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था- क्लेम से निपटने में 80 दिन लग सकते हैं

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को 80 दिन लग सकते हैं।

6 साल में 400 परमाणु हथियार बनाए, 2030 तक 1000 से ज्यादा होंगे

चीन ने 2020 में छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया: अमेरिका

राष्ट्रबाण | वॉशिंगटन | एजेंसी | rashtrabaan.in

अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने छह साल पहले 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था।

अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव क्रिस्टोफर येव ने सोमवार को कहा कि 22 जून 2020 को चीन के पश्चिमी इलाके में स्थित लोप नूर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर पर एक विस्फोट हुआ था।

यह विस्फोट 2.75 तीव्रता का था, जिसकी जानकारी पड़ोसी देश कजाकिस्तान के स्टेशन से मिली। येव ने इसे एक परमाणु विस्फोट बताया। उन्होंने कहा कि भूकंप माइनिंग विस्फोट से अलग थे। यह एक सिंगल फायर एक्सप्लोजन की तरह था, जो परमाणु परीक्षण की निशानी है। येव ने कहा कि चीन ने जानबूझकर अपनी परमाणु ताकत बढ़ाई है। उन्होने बताया कि 2020 से अब तक चीन के परमाणु हथियार 200 से बढ़कर 600 से ज्यादा हो गए हैं। अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 1,000 से ऊपर पहुंच जाएगी।

अमेरिका, रूस और चीन के बीच तीन तरफा समझौता चाहते हैं ट्रम्प

पिछले कुछ सालों में परमाणु हथियारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई विवाद हुए हैं। 2010 में अमेरिका और रूस ने न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती थी। इस संधि के तहत दोनों देशों को अपने परमाणु वारहेड्स को 1,550 तक सीमित रखना था और मिसाइलों और बॉम्बर्स की संख्या पर भी पाबंदी थी। इस संधि में रूस के गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों, जैसे छोटी दूरी के हथियारों को शामिल नहीं किया गया था।

अमेरिका का दावा- चीन अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर रहा

यह दावा ऐसे समय में आया है जब इस महीने अमेरिका और रूस के बीच का आखिरी बड़ा परमाणु समझौता न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो गया है। इस संधि के खत्म होने के साथ ही दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के हथियारों पर लगी सीमाएं हट गई हैं, जिससे नए न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका अब चीन और रूस से पारदर्शिता और खतरनाक हथियारों को सीमित करने की मांग कर रहा है।

राष्ट्रबाण
सिवनी, बुधवार 25 फरवरी 2026

शहडोल राष्ट्रबाण

• ब्यौहारी • जयसिंघनगर • सोहागपुर • गोहपारु • बुढार • जैतपुर

शहर में धड़ल्ले से बिना नंबर की डग्गी वाहनों से रेत सप्लाई

टेंडर न होने से आपूर्ति पर सवाल, खनिज व पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर प्रश्न

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

शहर में इन दिनों बिना नंबर की डग्गी वाहनों से खुलेआम रेत की सप्लाई किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्य मार्गों से लेकर रिहायशी कॉलोनियों तक दिनभर और तड़के सुबह रेत से भरे वाहन बेखौफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि रेत खनन का अधिकृत टेंडर जारी न होने के बावजूद बाजार में पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर रेत की आपूर्ति कहाँ से

और किसके संरक्षण में हो रही है। जानकारों की माने तो बिना नंबर प्लेट की डग्गी गाड़ियां सीधे निर्माण स्थलों तक रेत पहुंचा रही हैं। कई बार शिकायतें भी की गई लेकिन कार्रवाई सीमित स्तर तक ही सिमटती नजर आई। सूत्रों की माने तो आसपास की रेत खदानों से अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और डग्गी वाहनों के माध्यम से शहर तक सप्लाई की जा रही है।

जिम्मेदार मौन, कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि टेंडर प्रक्रिया अभी लंबित है तो बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में रेत कैसे उपलब्ध हो रही है? क्या अवैध खनन को किसी स्तर पर संरक्षण प्राप्त है? जानकारों की माने तो बिना वैध रॉयल्टी और दस्तावेजों के रेत परिवहन पूरी तरह नियमों के विपरीत है। इसके बावजूद प्रभावी और व्यापक कार्रवाई का अभाव कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है।

सोहागपुर थाना में बदले प्रभारी, फिर भी रेत पर ढील क्यों?

इसी बीच सोहागपुर थाना में प्रभारी बदल चुके हैं और सख्त छवि के लिए पहचाने जाने वाले थाना प्रभारी अरुण पांडेय की पदस्थापना के बाद अन्य अवैध खनिज मामलों में कार्रवाई भी देखने को मिली है। क्षेत्र में उनके साफ-सुथरे और कड़े रुख की चर्चा भी है। लेकिन रेत से भरी बिना नंबर की गाड़ियों और कथित अवैध खदानों पर अपेक्षित कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जब अन्य खनिज मामलों में सख्ती दिखाई गई है तो फिर रेत परिवहन और अवैध उत्खनन पर निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं।

किसके संरक्षण में संचालित हो रही खदान

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अधिकृत टेंडर के अभाव में रेत खदानों का संचालन किसके निर्देश पर हो रहा है। क्या यह पूरा खेल राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है या फिर जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय की कमी इसका कारण हो सकता है। शहर में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों के बीच रेत की बढ़ती मांग का फायदा उठाकर अवैध आपूर्ति का नेटवर्क सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। आम नागरिकों ने पारदर्शी जांच, सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है ताकि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सके और शासन को राजस्व हानि से बचाया जा सके।

पांडवनगर मार्ग पर अव्यवस्थित पार्किंग से जाम

प्रशासनिक आवास और विद्यालय के बीच रोज बनती अव्यवस्था, कार्रवाई के अभाव में बढ़ी परेशानी

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

शहर का मॉडल रोड से पांडवनगर जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लगातार जाम की समस्या से जूझ रहा है। सड़क किनारे संचालित दुकानों के बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से वाहन सीधे मार्ग पर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। स्थिति यह है कि दिन में कई बार लंबा जाम लग जाता है और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दुकानों के सामने दोपहिया और चारपहिया वाहनों की कतार लग जाती है। कई दुकानों के पास निजी पार्किंग स्थल नहीं है फिर भी सड़क पर ही वाहन खड़े कर ग्राहकों को सुविधा दी जा रही है। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहनों को

नगर पालिका और यातायात विभाग की चुप्पी

स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो नगर पालिका द्वारा दुकानों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है और न ही यातायात विभाग नियमित अभियान चला रहा है। यदि दुकानों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। नागरिकों ने मांग की है कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर सख्ती की जाए, नियमित चालानी कार्रवाई हो और आवश्यकता पड़े तो नो पार्किंग जोन घोषित कर स्पष्ट संकेतक लगाए जाएं। जब तक जिम्मेदार विभाग समन्वित और सख्त कदम नहीं उठाते, तब तक मॉडल रोड पांडवनगर मार्ग पर जाम की समस्या से राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।

निकलने में कठिनाई होती है।

विद्यालय और अधिकारियों के आवास के बीच बढ़ी समस्या

इसी मार्ग पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय भी संचालित है, जहां सुबह और दोपहर के समय विद्यार्थियों को छोड़ने और लेने आने वाले वाहनों की भीड़ अलग से लगती है। इसके अलावा पास में प्रशासनिक अधिकारियों के आवास भी स्थित हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहना आवश्यक है लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं।अभिभावकों की माने तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात नियंत्रण जरूरी है लेकिन अव्यवस्थित पार्किंग और जाम के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार एम्बुलेंस या आपातकालीन वाहन भी जाम में फंस जाते हैं जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।

रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट के सामने हालात और गंभीर

इसी मार्ग पर स्थित रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट के बाहर भी पार्किंग व्यवस्था न होने को जाम का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों की माने तो यहां ग्राहकों के वाहन तो सड़क पर खड़े होते ही हैं, साथ ही बड़ी मालवाहक गाड़ियों द्वारा सामान उतारने का कार्य दुकान के सामने पर किया जाता है। लेकिन कई बार जब बड़े ट्रक या लोडिंग वाहन सड़क किनारे खड़े होकर माल उतारते हैं तो कुछ समय के लिए पूरा मार्ग संकरा हो जाता है। ऐसे में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है। व्यस्त समय में यह स्थिति और भी विकट हो जाती है।

मेटरनिटी ओटी की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, गायनिक विभाग के डॉक्टरों ने सौंपा सामूहिक ज्ञापन

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

जिला चिकित्सालय के मेटरनिटी विंग में इन दिनों कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। गायनिक विभाग के सभी चिकित्सकों ने मेटरनिटी ऑपरेशन थियेटर में पदस्थ एक नर्सिंग अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए सिविल सर्जन को सामूहिक ज्ञापन सौंपा है। चिकित्सकों ने संबंधित नर्स को मेटरनिटी ओटी से हटाकर किसी अन्य वार्ड या विभाग में पदस्थ किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में डॉक्टरों ने कहा कि मेटरनिटी ओटी में तैनात नर्सिंग अधिकारी द्वारा ऑपरेशन संबंधी कार्यों में अपेक्षित सहयोग और रुचि नहीं ली जा रही है। विशेष रूप से सर्जरी के दौरान केस असिस्ट करने में लापरवाही बरतने की बात कही गई है। चिकित्सकों का कहना है कि कार्यकुशलता और व्यवहार में कमी के कारण सामान्य मामलों में भी अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे मरीजों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। डॉक्टरों ने ज्ञापन में बताया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की जटिल स्थिति निर्मित होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित नर्सिंग अधिकारी की होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्य में उदासीनता के कारण अन्य नर्सिंग स्टाफ पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। ज्ञापन पर मेटरनिटी विंग के समस्त चिकित्सकों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ ने कहा कि अस्पताल में स्टाफ का रोटेशन प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। ड्यूटी लगाना या बदलना प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी फिलहाल अवकाश पर हैं और आवश्यकतानुसार नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि उक्त नर्स पूर्व में भी सर्जरी ओटी से ड्यूटी बदले जाने को लेकर विवादों में रही है। बताया जाता है कि उस समय ड्यूटी परिवर्तन के विरोध में कुछ चिकित्सकों और संबंधित नर्स ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला शिकायतों तक पहुंचा। वर्तमान में इस प्रकरण की जांच सीएमएचओ कार्यालय में लंबित बताई जा रही है।

कमिश्नर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

कमिश्नर संभाग श्रीमती सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में कमिश्नर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।जनसुनवाई में शहडोल संभाग के दूर-दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं एवं शिकायतें कमिश्नर के समक्ष रखीं। कमिश्नर ने सभी आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं तथा उनके निराकरण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उमरिया जिले के ग्राम कछौहा निवासी रामभजन पटेल ने शासकीय भूमि में निर्मित तालाब से अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम बिरसिंहपुर निवासी शिवदास मेहरा ने भूमि पर कब्जा दिलाने, शहडोल जिले के ग्राम बिरौड़ी निवासी रामसुंदर चर्मकार ने संबल योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन दिया। इसी प्रकार ग्राम देवदहा निवासी शेषराम ने ग्राम देवदहा में बैगा बहुल क्षेत्र होने के कारण आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराए जाने, ग्राम झिरिया निवासी गायत्री बैगा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु नियुक्ति पत्र दिलवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रेषित करते हुए निर्देश दिए कि प्रकरणों का शीघ्र, निष्पक्ष एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

शहडोल में तीन दिन तक होगा विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा कर दिए निर्देश, पीएचसी-सीएचसी स्तर पर होगी स्क्रीनिंग

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

संभागीय मुख्यालय स्थित संभावित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 13, 14 एवं 15 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तृत समीक्षा की। यह शिविर रोटरी क्लब एवं राज कृष्ण तंखा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

सभी व्यवस्थाएं पूर्व से रहें सुनिश्चित

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिविर के आयोजन से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा शिविर में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मार्च माह में संभावित गर्मी को देखते हुए पेयजल, छायादार बैठक व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही कैंप स्थल पर साफ-सफाई, चलित शौचालय, वाहन पार्किंग एवं फायर ब्रिगेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

कलेक्टर ने अधिकारियों को शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि ऑटो एवं बसों में पोस्टर चस्पा कराए जाएं तथा नगरपालिका की कचरा गाड़ियों के माध्यम से भी मुनादी कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीज शिविर का लाभ उठा सकें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग ग्राम स्तर से लेकर पीएचसी एवं सीएचसी स्तर पर कराई जाएगी ताकि शिविर में गंभीर एवं चिन्हित मरीजों को समुचित उपचार मिल सके।

ऑपरेशन थियेटर व परिवहन व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में मेडिकल स्टाफ, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, ऑपरेशन थियेटर एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, मरीजों के लिए परिवहन सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

यह रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवम प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ सहित रोटरी क्लब, राजकृष्ण तन्खा फाउंडेशन के सदस्य एवं निजी अस्पतालों के संचालक उपस्थित रहे।

अमृत योजना 2.0 : सभी पेयजल परियोजनाएं समय-सीमा में पूरी करें : कमिश्नर

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों में अमृत योजना 2.0 के तहत चल रही नल जल योजनाओं, पाइपलाइन विस्तार और घर-घर नल कनेक्शन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं में देरी हो रही है, उनके लिए साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाया जाए।

ठेकेदारों पर निगरानी और पैनाल्टी

कमिश्नर ने निर्देश दिए कि ठेकेदारों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जो ठेकेदार काम में रुचि नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर पैनाल्टी लगाई जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें बरखास्त करने की कार्यवाही की जाए। बैठक में संयुक्त संचालक नगरीय निकाय आर. पी. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री और नगरीय निकायों के उपयंत्री उपस्थित रहे।

वाटर बॉडी और अमृत पार्क के निर्माण पर जोर

कमिश्नर ने कहा कि नगरीय निकायों में वाटर बॉडी का निर्माण 15 मार्च तक पूरा किया जाए। इसके साथ ही जिन निकायों में अमृत पार्क बनाए जा रहे हैं, उन परियोजनाओं को भी समय-सीमा में पूर्ण कराना होगा।

स्वच्छता और कचरा प्रबंधन

कमिश्नर श्रीमती गुप्ता ने नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सक्रिय करने और शहडोल नगरपालिका में कचरा प्रबंधन के तहत लगाए जा रहे प्लांट की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम जनता को पृथक-पृथक कचरा संग्रहण के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया।

सीवरेज और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

कमिश्नर ने नगर की सीवरेज लाइन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मार्च माह तक इसे पूरा कराया जाए और देरी करने वाले ठेकेदारों पर पैनाल्टी लगाई जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत डीपीआर बनाने का कार्य शीघ्र पूरा करने और सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र हितग्राही का आवास बिना पर्याप्त कारण के निरस्त नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लक्ष्य

बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

जैविक खेती तकनीक और स्थानीय संसाधनों के उपयोग का लिया जायजा

लमरो में प्राकृतिक खेती क्लस्टर का संयुक्त सचिव ने किया निरीक्षण, किसानों से हुए रूबरू

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

भारत सरकार के संयुक्त सचिव और प्रधानमंत्री पीएम धन-धान्य योजना के नोडल अधिकारी दीपक मिश्रा ने सोहागपुर जनपद पंचायत के ग्राम लमरो में प्राकृतिक और जैविक खेती क्लस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी खेती के तरीकों, लागत कम करने के उपाय और स्थानीय संसाधनों के उपयोग की जानकारी प्राप्त की।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप पद्धति से किसानों को हो रहा लाभ

किसान मोहन पटेल ने बताया कि उन्होंने आठ एकड़ में उद्यानिकी

फसलों की खेती पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिद्धांत के तहत शुरू की है। उन्होंने कहा कि पहले वे बटाई में खेत लेकर खेती करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र और किसान कल्याण विभाग के मार्गदर्शन से नई तकनीक अपनाई। उन्होंने मल्चिंग और ड्रिप एरिगेशन के माध्यम से मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, रेरूआ, कुम्हड़ा आदि उगाने शुरू किए। इसके परिणामस्वरूप सालाना सात से आठ लाख रुपये तक का लाभ हो रहा है।

जैविक खेती का व्यापक प्रचलन

गांव के किसान भोल्ली सिंह ने बताया कि गांव में बैगा और भुमिया जनजाति के 107 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गेहूं, चना, धान, अरहर सहित दैनिक उपयोग की फसलें रासायनिक उर्वरक के बिना उगाई जा रही हैं। मटका खाद, वर्मी कम्पोस्ट और जैविक कीटनाशक का उपयोग करके खेती की जा रही है। जैविक कीटनाशक नीम, कहुआ, बेसरम, धतूरा, सीताफल आदि से तैयार किया जाता है।

कृषि सखियों ने प्रशिक्षण एवं समर्थन दिया

किसान सखी श्रीमती बिरमतिया बाई ने बताया कि यहां कृषि सखियों की सीआरपी बनाई गई है जो ग्रामीणों को प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

संयुक्त सचिव ने की सराहना

संयुक्त सचिव श्री मिश्रा ने मटका खाद, वर्मी कम्पोस्ट और जैविक कीटनाशक निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और जनजातीय किसानों द्वारा अपनाई गई प्राकृतिक खेती पद्धति की सराहना की। उन्होंने किसानों से खेती की लागत में कमी और स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर विशेष चर्चा की।

बीआरसी और प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना

उप संचालक कृषि अनुराग पटेल ने बताया कि ग्राम लमरो को प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के तहत बीआरसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक बी.के. प्रजापति ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों को लागत कम करने और अपनी उपज का अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल रही है।

यह रहे उपस्थित

इस अवसर पर ग्रामीण किसान, कृषि सखियां, विभागीय अमला, संयुक्त संचालक शिक्षा उमेश धुर्वे, उप संचालक आर.के. मंगलानी, एपीसी अरविंद कुमार पाण्डेय एवं कृषि विभाग का मैदानी अमला उपस्थित रहा।

राष्ट्रबाण
सिवनी, बुधवार 25 फरवरी 2026

राजधानी राष्ट्रबाण

● बैरसिया ● हुजूर ● कोलार

भरवारा विवाद: 8 सस्पेंड, लेकिन थाना प्रभारी पर खामोशी क्यों?

वीडियो में दिखे टीआई, फिर भी बच गए! छोटे पुलिसकर्मी बने बलि का बकरा?

नरसिंहपुर| संवाददाता
rashtrabaan.in

स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के भरवारा गांव में हुए विवाद के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा द्वारा 8 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध की गई निलंबन की कार्रवाई शुरू से ही विवादों के घेरे में है। पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाही के बाद जमकर वाहवाही लूटी किन्तु साथ ही इस कार्रवाई ने पुलिस की जवाबदेही और निष्पक्षता पर कई तीखे सवाल खड़े भी किये। प्रशासन द्वारा इसे अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन गहराई से देखने पर इसमें कई प्रशासनिक खामियां और पक्षपात की बू नजर आ रही है। वायरल वीडियो ने खोली पोल, मौके पर मौजूद थे थाना प्रभारी सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसने पुलिस विभाग के दावों की हवा निकाल दी थी। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिस समय आरोपी वारदात को अंजाम देकर निकले तब वहाँ स्टेशनगंज थाना प्रभारी स्वयं वहां मौजूद रहकर पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे थे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब पूरी टीम का नेतृत्वकर्ता स्वयं वहां मौजूद था, तो दंड का पात्र केवल निचला अमला ही क्यों बना? क्या थाना प्रभारी की मौजूदगी में आरक्षक

प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति पर उठते सवाल

जनता अब पुलिस अधीक्षक से यह स्पष्टीकरण मांग रही है कि क्या जिले में कानून की व्याख्या पद के हिसाब से बदल जाती है? क्या थाना प्रभारी को बचाने के लिए जानबूझकर जांच की दिशा मोड़ी गई है? इस पूरे प्रकरण ने पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यदि पुलिस वास्तव में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना चाहती है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि इस पूरे विवाद के असली सूत्रधार कौन थे और उन पर अब तक क्या वैधानिक कार्रवाई की गई है।

लापरवाही पर एसपी का सख्त कार्रवाई -भरवारा विवाद मामले में 8 पुलिसकर्मी निलंबित

अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकते थे? एफआईआर पर भी सस्पेंस अपराध हुआ तो दोषी बाहर क्यों? इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल एफआईआर को लेकर है। यदि मौके पर स्थिति इतनी गंभीर थी कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण 8 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा, तो उन 20-22 उपद्रवियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? और यदि

डॉ ऋषिकेश मीणा, पुलिस अधीक्षक : क्या थानेदार को मिलेगा दण्ड?

सौरभ पटेल, थाना प्रभारी स्टेशन गंज : एसपी साहब के कर्म, बच गए हम!

एफआईआर दर्ज की गई है, तो अब तक कितने दोषियों की गिरफ्तारी हुई? प्रशासन की थ्योरी यहां उलझती नजर आ रही है, यदि अपराध इतना बड़ा था कि पुलिसकर्मियों की नौकरी पर बन आई, तो अपराधी अब तक आजाद क्यों घूम रहे हैं ? और यदि कोई बड़ा अपराध ही नहीं हुआ, तो कर्मचारियों पर यह दंडात्मक कार्रवाई किस आधार पर की गई?

छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश

जानकारों का मानना है कि केवल प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों को निलंबित करना प्रशासनिक न्याय की मंशा पर सवाल उठाता है। विभागीय नियमों के अनुसार, किसी भी घटना स्थल पर मौजूद सबसे वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए उत्तरदायी होता है। वायरल वीडियो में थाना प्रभारी की सक्रिय मौजूदगी यह साबित करती है कि मौके पर जो भी निर्णय लिए गए या नहीं लिए गए, उसके जिम्मेदार वे स्वयं थे। इसके बावजूद, केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक के सामने खड़े तीन सवाल

यदि एफआईआर का अभाव पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने अपराध नहीं रोका, तो वह अपराध क्या था? और यदि अपराध हुआ, तो उन 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया ? दोहरा मापदंड वायरल वीडियो में जब थाना प्रभारी स्वयं लाठी पकड़े भीड़ के बीच खड़े दिख रहे हैं, तो क्या उनकी उपस्थिति को लापरवाही की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए ? असली दोषियों को संरक्षण - क्या पुलिस विभाग केवल अपने ही कर्मचारियों को दंडित करके जनता को यह संदेश देना चाहता है कि असली उपद्रवियों और दंगाई तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की उसमें हिम्मत नहीं है ?

जबलपुर में मध्य प्रदेश का भविष्य कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन से हुई शुरुआत, विकास और सुशासन पर मंथन

जबलपुर| संवाददाता
rashtrabaan.in

छत्तीसगढ़ और लल्लूराम डॉट कॉम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ÷मध्य प्रदेश का भविष्य÷ कार्यक्रम का भव्य आयोजन जबलपुर में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर सहित शहर की अनेक प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के मंच प्रदेश के विकास और जनसंवाद को दिशा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने न्यूज़ 24 मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ और लल्लूराम डॉट कॉम की पहल को सराहनीय बताते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपने संबोधन में कहा कि शपथ लेते समय उन्होंने माँ नर्मदा की स्वच्छता का संकल्प लिया था, जिस पर प्राथमिकता से कार्य किया गया। उन्होंने दावा किया कि जबलपुर को वायु गुणवत्ता में दूसरा और स्वच्छता में पांचवां स्थान दिलाने में नगर निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतिक्रमण को चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में निरंतर कार्रवाई जारी है। विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा, अगर चर्चा है तो चर्चाएं चलनी चाहिए और स्पष्ट किया कि उनकी भूमिका तय करना पार्टी का कार्य है, उनका लक्ष्य केवल विकास है। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने कहा कि शहर के 79 वार्डों में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने विपक्ष को आंकड़ों के साथ बहस की चुनौती देते हुए कहा कि विकास केवल नगर निगम सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की प्रगति से जुड़ा है। उन्होंने मंत्री राकेश सिंह द्वारा प्रदेश में सड़क नेटवर्क विस्तार, बड़े फ्लाईओवर और रिंग रोड जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कानून व्यवस्था पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर उठे सवालों को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ मामलों में अपेक्षित स्तर पर काम नहीं हो पाया। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने गौ संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि गाय को पशु की श्रेणी से अलग कर विशेष विभाग बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सकारात्मक कार्य को ही सच्चा धर्म बताया। कार्यक्रम में विकास, सुशासन और सामाजिक सरोकारों पर सार्थक मंथन देखने को मिला।

इलाज के दौरान ट्रांसजेंडर होते हैं तय धारणा का शिकार

एम्स की रिसर्च- संवेदनशील व्यवहार और नीति सुधार से ही बदलेगा स्वास्थ्य अनुभव

भोपाल| संवाददाता
rashtrabaan.in

इलाज के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक पूर्वाग्रह (धारणा), भेदभाव, संवाद की कमी और लिंग-संवेदनशील सेवाओं के अभाव जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एम्स के हालिया अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। शोध में स्पष्ट किया है कि केवल दवा और उपचार पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वास्थ्यकर्मियों का व्यवहार, सांस्कृतिक समझ और सम्मानजनक दृष्टिकोण मरीज के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक नीतिगत सुधार और विशेष प्रशिक्षण नहीं होगा, तब तक समावेशी स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना अधूरी रहेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया अहम शोध

यह निष्कर्ष एम्स भोपाल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एमएससी नर्सिंग छात्रा के शोध में सामने आया। इस शोध को राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोध प्रस्तुति 2026 में स्नातकोत्तर वर्ग में पहला स्थान मिला। सम्मेलन का आयोजन Symbiosis College of Nursing ने किया था। यह रिसर्च ट्रांसजेंडर समुदाय के स्वास्थ्य अधिकारों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ठोस कदम भी मानी जा रही है।

इन चुनौतियों का करना पड़ता है सामना

अध्ययन में पाया गया कि अस्पतालों में पंजीयन से लेकर परामर्श और उपचार तक कई स्तरों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को असहज परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन कारणों से कई लोग समय पर इलाज लेने से भी कतराते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और गंभीर हो सकती है।

व्यवहार बदले तो बदलेगा अनुभव

शोध में विशेष रूप से यह रेखांकित किया है कि स्वास्थ्यकर्मियों का संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार मरीज के अनुभव को पूरी तरह सकारात्मक बना सकता है। यदि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ सांस्कृतिक विविधता को समझें और संवाद में सावधानी बरतें, तो विश्वास का वातावरण बनता है। नीतिगत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्पष्ट दिशा-निर्देश और जवाबदेही की व्यवस्था जरूरी बताई गई है। बिना संरचनात्मक बदलाव के समावेशी स्वास्थ्य सेवा केवल एक विचार बनकर रह जाएगी।

कलेक्टर ने लोगों की सुनी शिकायतें एवं समस्याएं

निराकरण के दिए निर्देश

शहडोल| संवाददाता
rashtrabaan.in

कलेक्टर कार्यालय के सोन सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई आयोजित की गई। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनीं तथा उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में ग्राम देवरा निवासी संचू बैगा ने विधवा विवाह योजना की सहायता राशि दिलाने, ग्राम विचारपुर निवासी कालीचरण सेन ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रेलवे मिश्रित स्कूल शहडोल में अध्ययनरत पुत्री की विद्यालय शुल्क माफी कराने, ग्राम सिंहपुर निवासी पप्पू चर्मकार ने शासकीय भूमि का पट्टा दिलाने, शहडोल वार्ड क्रमांक-9 निवासी दुर्गावती सेन ने गरीबी रेखा में नाम जोड़ने तथा जैतपुर निवासी अजीज ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित करते हुए शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

होटल पर कार्रवाई से पहले निगम को मिले 20 लाख

भोपाल में प्रॉपर्टी-जल कर बकायादारों पर कार्रवाई; 2 संपत्ति कुर्क

भोपाल| संवाददाता
rashtrabaan.in

भोपाल नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर राशि बकाया होने पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को 2 संपत्ति कुर्क की गई। वहीं, एक होटल पर कार्रवाई से पहले ही संबंधित ने 20 लाख रुपए जमा करा दिए। इससे होटल पर कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को निगम के अमले ने वार्ड-80 के अल्टीमेट आर्केड निवासी तहसीन खान द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि 7 लाख 99 हजार 762 रुपए और अनिंग पाईंट के टी-9 तृतीय तल के बकायादार प्रशांत शर्मा, विजेंद्र शर्मा, दीपेश मलिक, दीप विजय अरोड़ा व प्रशांत नायक पर 1 लाख 30 हजार 472 रुपए बकाया होने पर कार्रवाई की। इन सभी की संपत्ति कुर्क की गई।

होटल पर 28 लाख रुपए बकाया

जोन-19 के अंतर्गत वार्ड-84 में 11 मिल चौराहे पर होटल आमेर ग्रीन है। इस पर 28 लाख रुपए संपत्तिकर बकाया था। इस स्थिति में कुर्की की कार्रवाई के लिए अमला यहां पहुंचा, लेकिन इससे पहले ही 20 लाख रुपए जमा कर दिए गए। वहीं, बाकी 8 लाख रु राशि लोक अदालत में जमा करने का आश्वासन दिया गया।

इधर, जल सुनवाई में 23 नमूने लिए गए

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद सरकार ने हर मंगलवार को जल सुनवाई करने का फैसला लिया। मंगलवार को भोपाल के सभी 85 वार्डों में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जल सुनवाई हुई। इस दौरान कुल 23 नमूने परीक्षण के लिए लोगों ने दिए। इन्हें 8 लैब में भेजा गया है। ताकि, पानी की जांच हो सके।

केन्द्रीय डायरेक्टर ने घर-घर दवा सेवन और जागरूकता पर दिया जोर

फाइलेरिया से बचाव हेतु एल्वेन्डाजोल का सेवन अनिवार्य

भोपाल| संवाददाता
rashtrabaan.in

फाइलेरिया (हाथी पांव) जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए एल्वेन्डाजोल और डीईसी टेबलेट का समय पर सेवन अनिवार्य है। इस दिशा में एम.डी.ए. एवं सामूहिक दवा सेवा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय डायरेक्टर फाइलेरिया डॉ. एस.के. रसानिया एवं डॉ. मनीषा ने सीएमएचओ कार्यालय के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए।

घर-घर जाकर कराएं दवा सेवन

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और गठित दल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर सभी पात्र लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित करें। केन्द्रीय डायरेक्टर ने कहा कि फाइलेरिया किसी को भी हो सकता है, इसलिए स्वयं दवा का सेवन करें और अपने परिवार व संपर्क में आने वाले लोगों को भी सेवन के लिए जागरूक करें।

ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण

इस दौरान डॉ. रसानिया ने जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पड़मनिया, फतेहपुर और सुंदरी का दौरा कर दवा सेवन अभियान का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करने के लिए प्रेरित किया।

दवा खुराक और दिशा-निर्देश

केन्द्रीय डायरेक्टर ने बताया कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इस अभियान से छूटेंगे। अन्य सभी लोगों को निर्धारित मात्रा में डीईसी और एल्वेन्डाजोल की टेबलेट खाली पेट नहीं, बल्कि निर्देशानुसार चबाकर खानी होगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित

इस अवसर पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील स्थापक, जिला मलेरिया अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद नामदेव, जिला व्ही.बी.डी. सलाहकार श्री शिवशंकर शुक्ला सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया।

भोपाल गोमांस के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग

भोपाल| संवाददाता
rashtrabaan.in

भोपाल के आधुनिक स्लॉटर हाउस में मिले गोमांस के मुद्दे को लेकर नगर निगम का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठी है। इसे लेकर बीजेपी पार्षद विलास राव घाड़गे ने महापौर मालती राय को पत्र लिखा है। कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया, भोपाल नगर क्षेत्र में गो हत्या की घटना से लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों है। यह विषय केवल धार्मिक आस्था, गो संवर्धन से ही नहीं जुड़ा, बल्कि कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और नगर सरकार की जवाबदेही से भी संबंधित है। इसलिए नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 30 के तहत महापौर को आवश्यक परिस्थितियों में विशेष बैठक बुलाने का विधिक अधिकार है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए महापौर जल्द ही विशेष बैठक बुलाए और चर्चा करें।

महापौर को लिखे पत्र में वार्ड-34 से पार्षद घाड़गे ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

जहांगीराबाद थाना प्रभारी मान सिंह चौधरी ने 24 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज की। इसमें 7 दिन पहले, 17 दिसंबर को कंटेनर नंबर यूपी 15 जेटी 4286 में मांस मिलने का हवाला दिया।

राष्ट्रबाण
सिवनी, बुधवार 25 फरवरी 2026

बैतूल राष्ट्रबाण

• मुलताई • बैतूल बाजार • आमला • भैंसादंड • सारणी • बोरदई • आठनेर

प्रसूता के पेट पर घूंसे मारे...नवजात की हुई मौत: महिला दर्द से तड़प रही थी

स्टाफ सो रहा था, कहा-पाप किया इसलिए नहीं हो रहा बच्चा

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

मध्य प्रदेश के बैतूल जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में नवजात की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि नर्स ने प्रसूता के पेट पर घूंसे मारे। मेडिकल स्टाफ ने महिला के पेट पर दबाव डाला, जिससे नवजात की जान गई। अभद्र टिप्पणी की। प्रसूता से कहा कि तुमने कोई पाप किया होगा, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है।

घटना से पत्नी सदमे में, मानसिक स्थिति बिगड़ी

नवजात के पिता योगेश यादव के मुताबिक, प्रसव के दौरान स्टाफ ने असंवेदनशील व्यवहार किया। अपमानजनक टिप्पणियां भी कीं। प्रसव के समय महिला के पेट पर दबाव डाला गया, जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। मेरी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। योगेश यादव के मुताबिक, घटना के बाद पत्नी की तबीयत और मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। वे महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के कहने पर फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में ही चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक घटना 20 फरवरी की रात की है। परिवार का कहना है कि प्रसूता को तेज दर्द होने के बावजूद ड्यूटी पर मौजूद नर्स और स्टाफ ने समय पर ध्यान नहीं दिया। ड्यूटी में तैनात नर्स रात में ढाई बजे सो रही थी, उसे उठाया गया तो चिढ़कर बदसलूकी की।

3 डॉक्टर्स की टीम करेगी जांच, नर्स और स्टाफ को नोटिस

बैतूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिविल सर्जन जगदीश घोरे ने कन्फर्म किया कि महिला के पेट में घूंसा मारा गया था। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच के लिए तीन डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है।

ड्यूटी पर मौजूद नर्स और क्लास ढ्ढ्ढ स्टाफ को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनूपपुर में पटवारियों पर कार्रवाई, प्रदेशभर में आक्रोश

बैतूल पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 27 फरवरी से हड़ताल की चेतावनी

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

बैतूल

अनूपपुर जिले में पटवारियों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में प्रदेशभर के पटवारियों में है। मंगलवार को मध्यप्रदेश पटवारी संघ की बैतूल जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकारी जिलाध्यक्ष अवधेश वर्मा, संरक्षक जितेंद्र पवार के नेतृत्व में पटवारियों ने राजस्व विभाग मध्यप्रदेश के प्रमुख सचिव और आयुक्त भू-अभिलेख (ष्टरुक्र) के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

संघ ने ज्ञापन में बताया कि अनूपपुर जिला प्रशासन द्वारा पटवारियों का लगातार आर्थिक, मानसिक और प्रशासनिक उत्पीड़न किया जा रहा है। अनूपपुर में कई पटवारियों का वेतन महीनों से रोका गया है, बिना किसी अपील के अर्थदंड लगाए गए हैं और 30 से अधिक पटवारियों को बिना नोटिस के निलंबित किया गया है।

प्रदेशभर के पटवारी चरणबद्ध आंदोलन

बैतूल इकाई ने इन कार्रवाइयों को तानाशाही करार देते हुए कहा कि वेतन पर कर्मचारी और उसके परिवार का अधिकार होता है, जिसे अनूपपुर कलेक्टर द्वारा अनुचित रूप से रोका गया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि अनूपपुर जिले के पटवारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, तो प्रदेशभर के पटवारी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। घोषणा के अनुसार, 25 और 26 फरवरी को प्रदेशभर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलाध्यक्ष अनूपपुर कलेक्टोरेट का घेराव करेंगे। यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो 27 फरवरी से प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बैतूल जिले के दर्जनों पटवारी मौजूद रहे।

बैतूल में बस ऑपरेटर्स 2 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे

नई स्टेट कैरेज नीति के विरोध में बैतूल में ज्ञापन दिया

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

बैतूल जिले के बस संचालक राज्य सरकार की नई स्टेट कैरेज नीति के विरोध में 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को जिला बस यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बस संचालकों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा लाई जा रही नई स्टेट कैरेज नीति निजी बस व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। इस नीति के तहत स्टेट कैरेज परमिट जारी होने से निजी बस संचालकों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।

यूनियन से जुड़े विकास आर्य ने बताया कि यह नीति प्रदेश के कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। इसके तहत ये उद्योगपति छोटे बस ऑपरेटर्स से बसें लेकर उनका संचालन करेंगे। हालांकि, बसों का परमिट, रोड टैक्स और अन्य सभी प्रक्रियाएं बस ऑपरेटर को ही पूरी करनी होंगी, साथ ही उद्योगपति को एक निश्चित रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। यूनियन का आरोप है कि यह नीति छोटे ऑपरेटर्स को खत्म कर देगी।

यूनियन ने सरकार से प्रस्तावित नीति को वापस लेने और निजी बस संचालकों के हितों को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया, तो 2 मार्च से प्रदेशभर में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में विकास आर्य, संजू गायत्री, शरद वागदरे, अनिल पोटे, योगेश पोटे और अशोक राठौर सहित यूनियन के अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

भीलावाड़ी में शासकीय भूमि विवाद में खड़ी फसल पर चलाई जेसीबी

1980 से काबिज सात परिवारों ने एफआईआर की मांग की

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

ग्राम भीलावाड़ी में शासकीय भूमि को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। खसरा नंबर 83/4 और 83/5 को लेकर चल रहे नामांतरण विवाद के बीच खड़ी फसल पर जेसीबी चलाने का मामला सामने आया है। वर्ष 1980 से भूमि पर काबिज होने का दावा कर रहे सात भूमि हीन परिवारों ने कलेक्टर से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव, धारा 250 मध्यप्रदेश राजस्व संहिता के प्रकरण और 29 अप्रैल 2025 से लंबित जनसुनवाई आवेदन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायतकर्ता रामकिशोर पिता चिरोंजी मेहरा उम्र 60 वर्ष, अखलेश पिता प्रेमलाल मेहरा उम्र 30 वर्ष, भाऊराव पिता मना खातरकर उम्र 45 वर्ष, अंगद पिता मना खातरकर उम्र 50 वर्ष, बबलू पिता झामलाल टेकाम उम्र 40 वर्ष, मनोज पिता जुग्गी मेहरा उम्र 40 वर्ष तथा लक्ष्मी पति छोटु मेहरा उम्र 60 वर्ष, सभी निवासी भीलावाड़ी तहसील जिला बैतूल ने संयुक्त आवेदन में बताया कि मौजा भीलावाड़ी के खसरा नंबर 83/4 रकबा 3.100 हेक्टेयर भूमि पूर्व में घास मद में दर्ज थी और वर्ष 1980 से 2000 तक के खसरा अभिलेखों में उनका कब्जा दर्ज रहा है। आवेदकों के अनुसार कलेक्टर बैतूल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 931/59 वर्ष 1999-2000 के आदेश दिनांक 19 जून 2000 से भूमि मंद घास से परिवर्तित होकर काबिज काश्त घोषित की गई थी।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मलकापुर निवासी राजेन्द्र वर्मा सहित अन्य ने बिना विधिसम्मत आदेश के खसरा नंबर 83/5 रकबा 3.024 हेक्टेयर में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसकी सूचना आवेदकों को नहीं दी गई। शिकायत में कहा गया है कि नाम दर्ज होने संबंधी कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

आवेदकों के अनुसार अनावेदकों ने खसरा नंबर 83/4 का सीमांकन कराया और उनके विरुद्ध धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत किया। दस्तावेज प्रस्तुत कराने के लिए आवेदन देने पर तहसीलदार द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराने का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है।

शिकायत में यह भी आरोप है कि 23 फरवरी 2026 को खसरा नंबर 83/5 के बजाय 83/4 की भूमि पर जेसीबी चलाकर खड़ी फसल उजाड़ने का प्रयास किया गया। आवेदक रामकिशोर ने बताया कि इस संबंध में 29 अप्रैल 2025 को जनसुनवाई में आवेदन दिया गया था, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

सातों आवेदकों ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर नामांतरण प्रक्रिया की वैधता की पड़ताल, संबंधित दस्तावेजों की जांच तथा आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कार्यालय किराये पर लेने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही तलाश

सारणी| संवाददाता
rashtrabaan.in

नवागत ब्लाक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कार्यालय खोलने के लिए किराये पर दुकान खोजने मे लगे हुए है. जिले से लेकर ब्लाक स्तर तक कांग्रेस पार्टी के पास कार्यालय नहीं है. बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश की सत्ता तक लंबा सफर तय किया। करीब 68 वर्षों तक देश की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब स्थानीय स्तर पर ऐसी हो गई है कि सारनी ब्लॉक में उसे अपना ठिकाना तक नसीब नहीं हो पाया है।हालात यह हैं कि कांग्रेस के नवनियुक्त सारनी ब्लॉक अध्यक्ष इन दिनों राजनीतिक रणनीति कम और ऑफिस खोजो अभियान ज्यादा चलाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जनता के मुद्दों से पहले पार्टी के लिए छत ढूंढना प्राथमिकता बन गया है

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस पार्टी ने कभी देश चलाया, आज बैतूल जिले मे कांग्रेस के पास कार्यालय

व्यवस्था तक नहीं है.सवाल यह भी उठ रहा है कि जब संगठन के पास खुद बैठने की स्थायी जगह नहीं,तो राजनीतिक लड़ाई की रणनीति आखिर कहाँ तैयार होगी,चाय की दुकान पर या कार्यकर्ताओं के ड्राइंग रूम में?दिलचस्प तुलना भी सामने आ रही है।एक तरफ कांग्रेस,जिसे बने 141 वर्ष हो चुके हैं,वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने महज एक दशक से कुछ अधिक समय में देशभर के राज्यों में अपने भव्य और आधुनिक कार्यालय खड़े कर दिए। राजनीतिक जानकार तंज कसते हुए कहते हैं कि कांग्रेस का इतिहास जितना लंबा है,बैतूल जिले में उसका वर्तमान उतना ही भटकता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि पार्टी पहले संगठन खड़ा करेगी या कार्यालय क्योंकि राजनीति में बिना पते की पार्टी को जनता कितनी गंभीरता से लेगी,यह आने वाला समय हीबताएगा। फिलहाल सारनी में कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव नहीं,बल्कि ऑफिस कहाँ बनेगा बना हुआ है।

छात्रावास अधीक्षक ने वरिष्ठ पत्रकार से की अभ्रदता

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास अधीक्षक द्वारा वरिष्ठ पत्रकार से अभद्रता किये जाने की शिकायत सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बैतूल से की है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें बताया कि सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक नारायण नगदे को जारी नोटिस के आधार पर खबर का प्रकाशन किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम सिन्हा ने बताया कि समाचार प्रकाशन का तात्पर्य छात्रावास में अनुशासन कायम करना एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए था, किन्तु अधीक्षक श्री नगदे द्वारा 23 फरवरी को रास्ते में रोककर छात्रों का स्टेटमेंट लेने के बहाने अपने कक्ष में बुलाकर मेरे साथ अभद्रता की। साथ ही धमकी देने संबंधी छात्रों से वीडियों बनाकर वायरल किया है, जोकि सरकारी कर्मचारी को नहीं किया जाना चाहिए था। पत्रकारों ने उक्त मामले की सूक्ष्मता से जांच कर छात्रावास अधीक्षक नारायण सिंह नगदे पर नियमानुसार कार्रवाई किये जाने की मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे।

अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, मौत :दस महीने पहले हुई थी शादी

बैतूल। बैतूल में जावरा के पास हुए एक सड़क हादसे में लाखापुर निवासी 25 वर्षीय सोनू कवड़े की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब सोनू अपने साथी रामदयाल के साथ अर्जुनवाड़ी से एक सगाई कार्यक्रम से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर से सोनू कवड़े सिर के बल सड़क पर गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। वहीं इस हादसे में उनके साथी रामदयाल को कोई चोटें नहीं लगी।

घायल सोनू को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोनू कवड़े की शादी दस माह पहले ही हुई थी। वह अपनी तीन बहनों के इकलौते भाई थे और उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था।

राजस्व, नपा और पुलिस ने तोड़ा था कमरा-बाउंड्रीवाल, फरियादी बोला- बिना सूचना तोड़फोड़ की

सड़क चौड़ीकरण: प्रशासनिक कार्रवाई पर कोर्ट का स्टे

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

बैतूल शहर के टिकारी क्षेत्र स्थित न्यू इंदिरा वार्ड में सड़क चौड़ीकरण को लेकर की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह मामला स्थानीय निवासी सुंदरलाल कड़वे की 0.058 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। रविवार को प्रशासन ने जेसीबी मशीन से यहां तोड़फोड़ की थी।

बिना सूचना तोड़फोड़ का आरोप

सुंदरलाल कड़वे ने न्यायालय में आवेदन देकर घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। उनका आरोप है कि 22 और 23 फरवरी को राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की टीम बिना किसी न्यायालयीन आदेश या पूर्व सूचना के उनके मकान के पीछे बने कमरे को तोड़ गई।

उन्होंने बताया कि उस कमरे में लेट-बाथ, नल फिटिंग और बिजली की व्यवस्था थी। साथ ही करीब 100 फुट लंबी बाउंड्रीवाल भी तोड़ दी गई।

रात में लगाया गया आवेदन

कड़वे के वकील ने रविवार रात को रात्रिकालीन आवेदन पेश किया। देर रात न्यायालय में पूरा स्टाफ उपलब्ध नहीं था, इसलिए सोमवार 23 फरवरी की सुबह सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया।
अब कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन वहां किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई टिकारी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण हटाने के तहत की जा रही थी। तहसीलदार पूनम साहू के नेतृत्व में टीम सतपाल आश्रम के सामने पहुंची थी और वहां कुल आठ अतिक्रमण हटाए गए थे। इस दौरान राजस्व आरआई श्री पोटफोड़े, नगरपालिका आरआई श्री परते और अखिल राय समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन पर किसी भी तरह की कार्रवाई रोक दी गई है। मामला अब न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

बैतूल से 7 साल का मासूम लापता :एक महीने बाद भी नहीं मिला सुराग,

पुलिस और एसडीआरएफ की तलाश जारी

बैतूल| संवाददाता
rashtrabaan.in

बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र स्थित चिल्कापुर गांव से 7 वर्षीय खुश माथनकर पिछले एक महीने से लापता है। 18 जनवरी को घर से बकरी लेने निकला खुश वापस नहीं लौटा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। खुश 18 जनवरी की शाम को स्कूल से घर लौटा था। उसने अपनी दादी को बताया कि वह बकरी लेने जा रहा है और घर से निकल गया। रास्ते में उसने अपने दोस्तों से भी यही बात कही थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। शाम तक जब खुश नहीं लौटा, तो परिजनों और ग्रामीणों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

19 जनवरी को परिजनों ने भैंसदेही पुलिस थाने में खुश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ने पांच दिनों तक इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया।

पुलिस ने आसपास के जिलों में खुश के पोस्टर लगाए हैं। अनाथालयों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर भी बच्चे की तस्वीरें वितरित की गई हैं। संदिग्धों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और महाराष्ट्र पुलिस की सहायता भी ली गई है। इन सभी प्रयासों के बावजूद, खुश का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

क्षेत्र में फैल रही बच्चा चोरी की अफवाहें

इस घटना के बाद क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाहें फैल गई हैं। इसके चलते लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से बच रहे हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और बच्चे के बारे में कोई भी ठोस जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

राष्ट्रबाण
सिवनी, बुधवार 25 फरवरी 2026

बालाघाट राष्ट्रबाण

● बैहर ● बिरसा ● कटंगी ● तिरोड़ी ● कटंगी ● खैरलांजी ● किरनापुर ● लालबर्रा ● लांजी ● परसवाड़ा ● वारासिवनी

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्या

145 आवेदकों ने दिये अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन

बालाघाट| संवाददाता
rashtrabaan.in

प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 24 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जीएस धुर्वे, श्री डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री राहुल नायक, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 145 आवेदक अपनी समस्या लेकर आए थे। जनसुनवाई में बालाघाट तहसील के ग्राम पंचायत खैरी निवासी 70 वर्षीय किसान श्री गौरीशंकर मोहारे धान खरीदी के दौरान धोखाधडी किये जाने की शिकायत लेकर आए थे। गौरीशंकर ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को उन्होंने धान उपार्जन केंद्र कुम्हारी (जरेरा) में 552 बोरी धान तौल के लिए दी थी, लेकिन उनके खाते में केवल 511 बोरी की ही एंट्री और भुगतान किया गया। शेष 41 बोरी की एंट्री दो दिन में करने का आश्वासन दिया गया, जो अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन केंद्र में कई बार संपर्क करने के बावजूद निरंतर केंद्र के कर्मचारियों द्वारा टालमटोल किया जा रहा हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान ने मामले की जांच कर शेष 41 बोरी धान की बकाया राशि दिलाने की मांग की है। इस प्रकरण में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के महाप्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

वारासिवनी तहसील के निवासी शुभम गजभिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि नही मिलने की शिकायत लेकर आए थे। शुभम का कहना था कि उसने 01 वर्ष पूर्व कन्या विवाह योजना अंतर्गत अपना विवाह किया और विवाह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किये किंतु आज दिनांक तक उसे इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त नही हुई है। इस प्रकरण में सामाजिक न्याय विभाग को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है।

वारासिवनी तहसील के ग्राम गर्रा की निवासी महक बिसेन पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की दावा राशि दिलाने की मांग लेकर आयी थी। महक ने बताया कि उसके पिता चित्रसेन बिसेन ने भारतीय स्टेट बैंक वारासिवनी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना खाता खुलवाया था। इस खाते में महक बिसेन को नामिनी नियुक्त किया गया था, जो उस समय नाबालिग थी। उसके पिता का 8 अगस्त 2021 को निधन हो चुका है। अब वह बालिग हो चुकी है। महक का कहना था कि उसने बैंक शाखा में जाकर खाते की जमा राशि एवं बीमा की दावा राशि प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसे अब तक राशि प्राप्त नहीं हो सकी। अतः महक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना की राशि एवं पिता के खाते में जमा राशि शीघ्र दिलाई जाए। इस प्रकरण में अग्रणी बैंक प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है।

वारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम डोंगरमाली निवासी अब्दुल समी शेख ग्राम सरपंच द्वारा अवैध धन वसूली किये जाने की शिकायत लेकर आए थे। अब्दुल का कहना था कि बाजार चौक डोंगरमाली में उनकी वर्षों पुरानी किराना दुकान थी, जिसे सरपंच द्वारा तीन नोटिस जारी कर हटवा दिया गया। अब्दुल ने बताया कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 90 दिनों के भीतर उसी स्थान पर नया कॉम्पलेक्स बनाकर एक लाख इकसठ हजार रुपये लेकर दुकान (कमरा) आवंटित की जाएगी, लेकिन उन्हें केवल 60 हजार रुपये की रसीद प्रदान की गई। साथ ही, कॉम्पलेक्स का निर्माण पूर्ण होने और अन्य दुकानों के आवंटन के बाद भी उन्हें अब तक दुकान आवंटित नहीं की गई है। इस प्रकरण में जनपद सीईओ वारासिवनी को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

जनसुनवाई में जनपद पंचायत बिरसा के जनपद सदस्य श्री लक्ष्मी मिथलेश पटले ग्राम बीजाटोला में हाट बाजार लगाये जाने की मांग लेकर आए थे। श्री पटले का कहना था कि उनके जनपद क्षेत्र में 10 से 15 गांव आते है, जिनका मुख्य गांव बीजाटोला ही है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की आवश्यक सामग्रियों सब्जी, किराना आदि जरुरतों की पूर्ति के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पडता है। अतः ग्राम बीजाटोला में साप्ताहिक हाट बाजार लगाने की अनुमति दी जाए एवं खनिज निधि से ग्राम पंचायत को बाजार शेड बनाने के लिए राशि दी जाए। इस पर मिथलेश को बताया गया कि बाजार लगाने के लिए ग्राम पंचायत को अनुमति की आवश्यकता नही है। बाजार शेड निर्माण के लिए जिला खनिज निधि के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है।

खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादण्ड की शीला टेम्भुर्ने विधवा पेंशन दिलाये जाने की मांग लेकर आयी थी। शीला का कहना था कि उसके पति सुरेंद्र टेम्भुर्ने की मृत्यु हो गई है। पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली विधवा पेंशन की राशि पिछले कुछ माह से उसे प्राप्त नही हो रही है। अतः उसे विधवा पेंशन की राशि शीघ्रता से दिलायी जाए। इस प्रकरण में बताया गया कि शीला के खाते में दिसम्बर 2025 तक की पेंशन जमा हुई है। जनवरी से उसकी पेंशन वेटिंग में है, जो शासन स्तर से लंबित है।

लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी के ग्रामीण पंचायत द्वारा आबादी घोषित भूमि को श्मशान घाट के लिए मरघट घोषित करने की मांग लेकर आए थे। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले 70 से 80 वर्षों से जिस भूमि पर दाह संस्कार किया जाता रहा है वह पहले बडे झाड का जंगल घोषित था। ग्राम पंचायत द्वारा पिछले 10 वर्ष से इस भूमि को आबादी घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार करने में असुविधा हो रही है। अतः आबादी घोषित भूमि को पुनः मरघट भूमि घोषित की जाए। इस प्रकरण में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है।

लालबर्रा तहसील के ग्राम बकोडा के गोदावरी करिया आर्थिक सहायता की मांग लेकर आयी थी। गोदावरी का कहना था कि 03 वर्ष पहले उसके पति की मृत्यु हो गई है। पति का संबल कार्ड भी नही था। उसके पास किसी अन्य योजना का भी कार्ड नही है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अतः उसे जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने रेडक्रास से गोदावरी को 10 हजार रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। लालबर्रा तहसील के ग्राम पिपरियॉ (घोटी) की संजना कावरे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि दिलाने की मांग लेकर आयी थी। संजना का कहना था कि उसने लगभग 08 माह पूर्व इस योजना में गर्भावस्था के दौरान अपना फार्म जमा किया था। लेकिन उसे अब तक इस योजना की राशि नही मिली है। उसने एक माह पूर्व सीएम हेल्प लाईन में भी इसकी शिकायत की है। लेकिन उस पर यह शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

उर्वशी एवं उसके दिव्यांग पुत्र ईश्वर बडगैया की समस्या का हुआ समाधान

बालाघाट| संवाददाता
rashtrabaan.in

लांजी तहसील के ग्राम दुल्हापुर की उर्वशी बडगैया एवं उसके दिव्यांग पुत्र ईश्वर बडगैया की समस्या का कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जनसुनवाई में समक्ष में सुनकर समाधान कर दिया है। कलेक्टर श्री मीना ने लांजी एसडीएम को निर्देशित किया है कि उर्वशी बडगैया एवं सुखदेव बडगैया के परिवार की भूमि का सीमांकन करें। इसके साथ ही उर्वशी बडगैया एवं उसके दिव्यांग पुत्र की स्थिति को देखते हुए सुखदेव एवं उर्वशी के मकान की दीवारों के बीच की भूमि पर दीवार भी बनाने के निर्देश दिये है, जिससे उर्वशी के मकान की दीवार को किसी तरह की क्षति न पहुंच सके। कलेक्टर द्वारा दिये गए निर्देश से उर्वशी एवं उसका दिव्यांग पुत्र ईश्वर बडगैया संतुष्ट हुए है और अब खुश है। उल्लेखनीय है कि ग्राम दुल्हापुर के सुखदेव बडगैया एवं शिकायतकर्ता उर्वशी बडगैया एक ही परिवार के सगे संबंधी है। सुखदेव बडगैया द्वारा अपने हिस्से में मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस पर उर्वशी बडगैया द्वारा आपत्ति ली जा रही है कि इससे उसके पुराने मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है। 24 फरवरी को कलेक्टर श्री मीना ने उर्वशी एवं उसके पुत्र ईश्वर की समस्या को गंभीरता से सुना और तत्काल लांजी एसडीएम को दूरभाष पर निर्देशित किया कि सुखदेव एवं उर्वशी की भूमि का सीमांकन कराए। इस दौरान उर्वशी के दिव्यांग पुत्र ईश्वर ने स्वीकार किया कि उसे कभी पेशी पर नही बुलाया गया है। उर्वशी ने बताया कि वह कम पढी लिखी है और उसे शासकीय प्रक्रिया की समझ नही है इस कारण से वह अपने दिव्यांग पुत्र को पेशी पर साथ लेकर आती रही है।

कक्षा 10 वीं की गणित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न

बालाघाट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मप्र भोपाल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 24 फरवरी को गणित विषय का प्रश्नपत्र जिले के 132 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी श्री अश्वनी उपाध्याय के नेतृत्व में गठित दल द्वारा 7 परीक्षा केंद्रों का सतत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय भंडेरी, मलाजखंड, पलेहेरा, मंडई, दमोह, उत्कृष्ट बिरसा तथा मानेगांव परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया गया। निरीक्षण दल ने केंद्रों पर व्यवस्थाओं, गोपनीयता एवं अनुशासन की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। 10वी बोर्ड परीक्षा में जिले में कुल 21,682 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 21,212 छात्र-छात्राएं परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 470 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान जिले में किसी भी प्रकार का नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

गोंदिया–जबलपुर रेललाइन के दोहरीकरण को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने 5236 करोड़ रुपये स्वीकृत किये

बालाघाट| संवाददाता
rashtrabaan.in

सेवातीर्थ में केन्द्रीय सरकार की पहली केबिनेट बैठक में गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाईन दोहरीकरण को मंजूरी मिल गई है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे रामायण सर्किट से लेकर नार्थ से साउथ तक का एक महत्वपूर्ण कॉरीडोर बताया है। इस दोहरीकरण का सबसे ज्यादा लाभ विकास के रूप में बालाघाट जिले मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गोंदियाङ्कजबलपुर रेललाइन के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान करते हुए 5236 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 24 फरवरी को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी के सतत प्रयासों से गोदिया-जबलपुर रेल लाईन के दोहरीकरण कार्य को सफलता मिली है। इस कार्य के पूर्ण होने से मध्यप्रदेश के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तकरीबन 231 किलोमीटर के गोंदिया-जबलपुर रेलवे दोहरीकरण का काम 5236 करोड़ रूपए से 5 साल में पूरा होगा। जिससे महाराष्ट्र के गोंदिया और मध्यप्रदेश के जबलपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान इस लाईन में आने वाले वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए 450 करोड़ रूपए अंडरपास और फेसिंग में खर्च किए जाएंगे। साथ ही रेलवे दोहरीकरण के इस काम में नर्मदा नदी में एक बड़े ब्रिज के साथ ही 65 मेजर और 369 माईनर ब्रिज बनाए जाएंगे। बालाघाटङ्कसिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि गोंदियाङ्कजबलपुर रेललाइन के दोहरीकरण के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए और विभिन्न स्तरों पर इस मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री से लगातार चर्चा कर संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा प्रभावी रूप से रखा, जिसके परिणामस्वरूप इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को स्वीकृति मिली है। सांसद श्रीमती पारधी द्वारा सांसद बनने के साथ ही लोकसभा में गोंदिया-जबलपुर रेलवेलाईन के दोहरीकरण के दृढता से मांग रखी थी और इसे प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार के लिए अत्यंत आवश्यक बताया था। सांसद श्रीमती पारधी के प्रयासों को सफलता मिल गई है और गोंदिया-जबलपुर रेललाईन के दोहरीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सांसद श्रीमती पारधी ने 5236 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

संजीवनी 108 की तत्परता से बची युवक की जान, मानवीय सेवा का प्रेरक उदाहरण

बालाघाट| संवाददाता
rashtrabaan.in

24 फरवरी 2026 की प्रातः लगभग 01 बजे वारा में बालाघाट रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना संजीवनी 108 एवं डायल 112 को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही संजीवनी 108 एम्बुलेंस बिना समय गंवाए तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और कुछ ही देर में मौके पर पहुंचकर घायल को प्राथमिक सहायता प्रदान की। घायल व्यक्ति की पहचान बाद में योगेश डहरवाल (उम्र 30 वर्ष), निवासी कटेगांव, तहसील लालबर्रा के रूप में हुई। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। संजीवनी 108 की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सिविल हॉस्पिटल वारासिवनी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक बताई। बेहतर उपचार के लिए उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया गया। इस दौरान संजीवनी 108 एम्बुलेंस के ईएमटी डॉ. महेंद्र राहंगडाले एवं पायलट योगेश राहंगडाले ने मानवीय संवेदनशीलता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए रास्ते भर घायल को आवश्यक प्राथमिक उपचार प्रदान किया और सुरक्षित रूप से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। समय पर मिले उपचार और त्वरित परिवहन के कारण योगेश डहरवाल की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह घटना एक बार फिर सिद्ध करती है कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों की सजगता, तत्परता और मानवीय संवेदनाएं किसी भी अनमोल जीवन को बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संजीवनी 108 के ईएमटी डॉ. महेंद्र राहंगडाले एवं पायलट योगेश राहंगडाले की इस सराहनीय पहल ने न केवल एक परिवार को बड़ी पीड़ा से बचाया, बल्कि मानव सेवा के सच्चे अर्थों को भी चरितार्थ किया है।

कन्या महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ

बालाघाट| संवाददाता
rashtrabaan.in

शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ, आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में प्राचार्य डॉ. निधि ठाकुर के मार्गदर्शन में 24 एवं 25 फरवरी 2026 को दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी का विषय 'भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम' रखा गया है। कार्यक्रम के प्रथम दिवस का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार पुष्पगुच्छ, श्रीफल एवं शाल भेंट कर किया गया। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी की संयोजक डॉ. सरोज घोडेश्वर ने संगोष्ठी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा की समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉ. अजय कुमार गुप्ता (विशेष कर्तव्य अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर) ने अपने उद्बोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा की वैश्विक उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। प्रथम विषय विशेषज्ञ के रूप में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं हिंदी साहित्य विभागाध्यक्ष डॉ. अवधेश कुमार ने भारतीय साहित्य और परंपरा के विविध आयामों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं द्वितीय विषय विशेषज्ञ डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव (प्राचार्य, शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल पी.जी. महाविद्यालय, सीहोरा) ने भारतीय ज्ञान प्रणाली की समसामयिक उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके पश्चात महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुनील कुमार मासुलकर एवं प्राचार्य डॉ. निधि ठाकुर ने भी अपने प्रेरक उद्बोधन दिए। कार्यक्रम के अंत में सहायक प्राध्यापक सुश्री प्रीति उइके ने आभार व्यक्त किया तथा कार्यक्रम का सफल संचालन श्री विजय कुमार तुरकर द्वारा किया गया। भोजनावकाश के पश्चात आयोजित तकनीकी सत्र में प्रतिभागियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। साथ ही महाविद्यालय परिसर में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं श्री अन्न प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसने उपस्थित जनों को भारतीय सांस्कृतिक एवं आहार परंपरा से परिचित कराया।

नियम विरूद्ध दिये गए पट्टे निरस्त करने एवं पट्टा देने वाले पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी

सीएम हेल्पलाईन की 100 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतों की कलेक्टर ने समक्ष में की सुनवाई

बालाघाट| संवाददाता
rashtrabaan.in

कलेक्टर श्री मृणाल मीना द्वारा प्रत्येक मंगलवार को सीएम हेल्प लाईन की निराकरण के लिए लंबित शिकायतों का रेंडमली चयन कर शिकायतकर्ता एवं निराकरण करने वाले अमले को समक्ष में बुलाकर सुनवाई की जाती है। इसी कडी में 24 फरवरी को कलेक्टर श्री मीना द्वारा 100 दिनों से अधिक की लंबित 05 शिकायतों की समक्ष में सुनवाई की गई और उनका निराकरण कराया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन एवं अधीक्षक भू-अभिलेख कमल नायर भी उपस्थित थे। वारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम मोहगांवखुर्द निवासी देवानंद पवार द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय में वर्ष 2014-15 में पारित आदेश की नकल मांगी गई थी, लेकिन तहसील कार्यालय द्वारा यह नकल अब तक उपलब्ध नही करायी गई थी। इस पर देवानंद पवार द्वारा सीएम हेल्प लाईन में शिकायत की गई थी और यह शिकायत 191 दिनों से लंबित थी। 24 फरवरी को समक्ष में सुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से नकल उपलब्ध नही कराने के कारण की जानकारी ली। इस संबंध में बताया गया कि पारित आदेश का रिकार्ड नही मिलने के कारण नकल उपलब्ध नही करायी जा सकी है। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने वारासिवनी तहसीलदार को सख्त निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यालय से रिकार्ड की प्रति प्राप्त की जाए और आवेदक को नकल उपलब्ध करायी जाए। लालबर्रा तहसील की ग्राम बांदरी के भीमराव चौरे द्वारा अपनी जमीन की सीमांकन एवं नक्शा अपडेट करने के लिए सीएम हेल्प लाईन मे शिकायत की गई थी। यह शिकायत 339 दिनों से निराकरण के लिए लंबित थी। इस प्रकरण की समक्ष में सुनवाई के दौरान संबंधित पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया कि मोतीराम भोंडेकर आबादी भूमि के पट्टे के लिए पात्र नही है। कलेक्टर श्री मीना ने दस्तावेजों के परीक्षण के बाद मोतीराम को स्पष्ट बता दिया कि उसे आबादी भूमि का पट्टा नही दिया जा सकता है और उसकी शिकायत को बंद किया जा रहा है। इस पर मोतीराम ने कहा कि वह भले ही आबादी भूमि के पट्टे के लिए पात्र न हो लेकिन गांव के सरपंच पति लेखचंद बघेले एवं देवेशरी को आवासीय भूमि के 2-2 पट्टे प्रदाय किये गए है। ऐसा नही होना चाहिए। इस पर कलेक्टर श्री मीना ने मौके पर ही दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि इन व्यक्तियों को 2-2 पट्टे प्रदाय किये गए है।

राष्ट्रबाण
सिवनी, बुधवार 25 फरवरी 2026

सिवनी राष्ट्रबाण

• बरघाट • छपारा • धनोरा • घंसौर • केवलारी • कुरई • लखनादौन • सिवनी ग्रामीण

पीएमश्री स्कूलों में लाखों का घोटाला: 200 बच्चों ने खाई 400 थालियां, 4 हजार का साउंड बॉक्स 44 हजार में खरीदा!

घोटाले की पाठशाला! भ्रष्टाचार के मास्टर?

सिवनी जिले के पीएमश्री स्कूलों में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। बच्चों के भोजन, अध्ययन सामग्री, खेल सामग्री और उपकरणों की खरीदी में कथित रूप से लाखों रुपए का गोलमाल किया गया। कहीं 200 बच्चों के नाम पर 400 थाली भोजन का बिल लगा, तो कहीं 4 हजार रुपए के साउंड बॉक्स के लिए 44 हजार रुपए का भुगतान दिखाया गया। शिकायतों की जांच के बाद तीन स्कूलों की फाइल कार्रवाई के लिए डीपीआई भोपाल भेज दी गई है।

शासकीय उच्चतर विद्यालय बूढ़ेना कला : भ्रष्ट सिस्टम ने किया शिक्षा के मंदिर को बदनाम।

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

शिवराज सिंह कुमरे
जिला शिक्षा अधिकारी : भ्रष्टों का बचाव, अज्ञानता से कर ली खरीदी।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएमश्री योजना के तहत चयनित स्कूलों को हर साल लाखों रुपए की राशि विकास और आधुनिक संसाधनों के लिए दी जाती है। लेकिन सिवनी जिले में यह योजना कथित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जिले के बरघाट क्षेत्र स्थित शासकीय पीएमश्री बूढ़ेना, पीएमश्री कन्या शाला बरघाट और शासकीय पीएमश्री खैरा पलारी स्कूल में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सबसे चौंकाने वाला मामला बूढ़ेना स्कूल का है, जहां तत्कालीन प्राचार्य शरण दास मैकेंजी पर आरोप है कि उन्होंने 200 विद्यार्थियों के भोजन के लिए 400 थाली का कच्चा बिल लगाकर करीब 80 हजार रुपए की राशि आहरित कर ली। सूत्रों के अनुसार, इस स्कूल में केवल भोजन ही नहीं बल्कि अन्य मदों में भी फर्जी बिल और वाउचर लगाकर रकम निकाली गई।

वहीं बरघाट पीएमश्री स्कूल में प्राचार्य शरला नरेती द्वारा 4 हजार रुपए कीमत के साउंड बॉक्स के लिए 44 हजार रुपए का बिल प्रस्तुत कर भुगतान का मामला सामने आया है। जांच में यह भी सामने आया कि खरीदी गई सामग्री का स्कूल में कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या भौतिक सत्यापन उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि यहां भी लाखों रुपए का गोलमाल हुआ है।

तीसरा मामला शासकीय पीएमश्री खैरा पलारी का है, जहां प्राचार्य जयंती मरावी पर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि निजी चंदे से संबंधित भुगतान को सरकारी खर्च में दर्शाया गया।

जांच के लिए भेजे दस्तावेज

इन तीनों मामलों की शिकायत मिलने के बाद प्राथमिक जांच की गई, जिसमें गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर संबंधित फाइलें आगे की कार्रवाई के लिए डीपीआई भोपाल भेज दी गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी शिवराज सिंह कुमरे ने पुष्टि की है कि तीनों स्कूलों के दस्तावेज उच्च स्तर पर परीक्षण के लिए भेजे गए हैं और जल्द ही सख्त कार्रवाई संभव है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पीएमश्री योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि बच्चों के भोजन, खेल सामग्री और शैक्षणिक संसाधनों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है, तो यह सीधे तौर पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी : यहां भ्रष्टों को मिलता है संरक्षण?

भ्रष्टाचार के गुरु

स्थानीय स्तर पर इस खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है शिक्षा के मंदिर में बैठे गुरुजन भ्रष्टाचार करने के मामले में भी गुरु है। यदि समय रहते शिकायत नहीं होती, तो यह सिलसिला और लंबा चलता। अब सबकी नजर डीपीआई भोपाल की कार्रवाई पर टिकी है कि क्या दोषियों पर कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा। जिले में शिक्षा व्यवस्था की साख दांव पर है। सवाल यह है कि जिन जिम्मेदारों को बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या वे ही संसाधनों में सेंध लगाकर व्यवस्था को खोखला कर रहे थे?

"अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या निलंबन, वसूली और आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

सत्ता की धमक के आगे नतमस्तक यातायात पुलिस!

भाजपा कार्यालय के सामने, जाम ही नियम है?

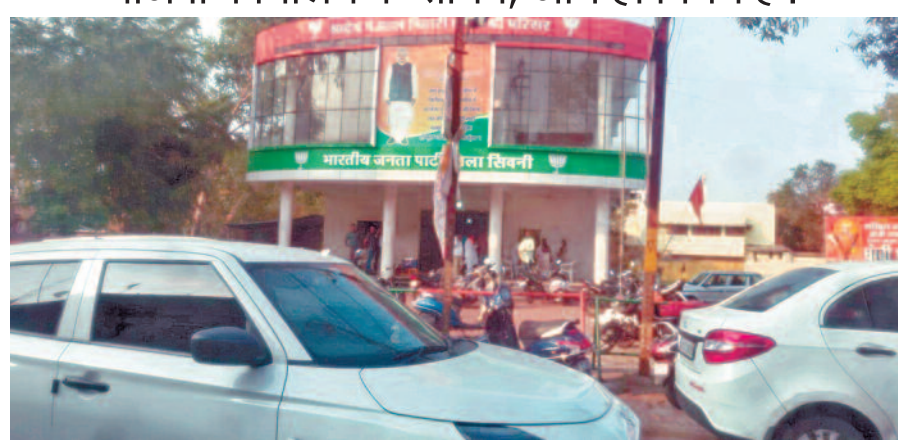

भाजपा कार्यालय के सामने लगे जाम का एक दृश्य।

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने इन दिनों यातायात व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। रसूखदारों की चमकती गाड़ियों और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण आम जनता जाम के जंजाल में फंसने को मजबूर है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि नियम-कायदों का डंडा चलाने वाली यातायात पुलिस यहाँ आकर पूरी तरह मेहरबान नजर आती है।

आम आदमी पर चालान, रसूखदारों को सलाम?

शहर के अन्य कोनों में हेलमेट और कागजों के नाम पर आम जनता की जेब ढीली करने वाली पुलिस भाजपा कार्यालय के सामने अंधी-बहरी हो गई है। यहाँ सड़क तक पसरे वाहनों के कारण पैदल चलना भी दूभर है, मगर मजाल है कि किसी पुलिसकर्मी की सीटी यहाँ बज जाए। वही सवाल यह उठता है कि क्या यातायात के नियम सिर्फ आम नागरिकों और गरीब ऑटो चालकों के लिए बने हैं? क्या भाजपा कार्यालय के सामने पार्किंग करना किसी भी कानूनी कार्रवाई से अघोषित छूट दिलाता है?

कार्रवाई या सिर्फ खानापूर्ति?

जब भी इस अव्यवस्था पर सवाल उठते हैं, कुछ दिन तक तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन ही दिया जाता है। लेकिन धरातल पर यह सिर्फ लिपा-पोती से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। जनता अब खुलेआम पूछ रही है कि क्या पुलिस विभाग केवल सत्ताधारियों का दरबारी बनकर रह गया है? वही कार्यालय के सामने गाड़ियाँ सड़क के बड़े हिस्से को घेर लेती हैं। जिससे घंटों जाम लगने के बावजूद पुलिस यहाँ केवल मूकदर्शक बनी रहती है। वही आम आदमी की गाड़ी दो मिनट खड़ी हो जाए तो यातायात विभाग चेतावनी देता नजर आता है, लेकिन यहाँ घंटों खड़े लग्जरी वाहनों पर नजर नहीं पड़ती। जिससे सिवनी की जनता यह जानना चाहती है कि क्या कभी इन माननीयों के वाहनों पर भी कानूनी डंडा चलेगा? या फिर रसूख के नाम पर यातायात पुलिस इसी तरह घुटने टेके रखेगी? अगर जल्द ही यहाँ ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो पुलिस की निष्पक्षता पर लगा यह दाग और गहरा होता जाएगा।

चिचोली के पटवारी 25 से अवकाश पर

बैतूल। अनूपपुर जिले में पटवारियों पर कथित प्रशासनिक तानाशाही के विरोध में तहसील चिचोली के पटवारियों ने 25 एवं 26 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा की है। साथ ही 27 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पूरा मामला अनूपपुर जिले के 38 पटवारियों पर अर्थदंड लगाए जाने, 30 पटवारियों को बिना नोटिस निलंबित करने तथा वेतनमान रोके जाने के आरोप से जुड़ा है, जिसे लेकर प्रदेशभर में आक्रोश की स्थिति बताई जा रही है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर तहसील अध्यक्ष सुखदेव गंगारे ने तहसीलदार चिचोली को दिए सूचना पत्र में उल्लेख किया है कि जिला अनुपपुर के समस्त पटवारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में चिचोली तहसील के सभी पटवारी उनके समर्थन में 25 एवं 26 फरवरी को अवकाश पर रहेंगे।

परीक्षाओं के दौरान शोर, पुलिस ने डीजे-वाहन जब्त किए

सिवनी में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

सिवनी पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजा रहे एक संचालक का साउंड सिस्टम और वाहन जब्त कर लिया।

कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि सोमवार 23 फरवरी की रात पुलिस को सूचना मिली थी। मिलन लॉन के सामने निर्धारित समय के बाद भी बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। सूचना मिलते ही एएसपी दीपक मिश्रा और एसडीओपी सचिन परते के मार्गदर्शन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में डीजे संचालक रामअवतार गेंडरे द्वारा नियमों का उल्लंघन कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना पाया गया।

पुलिस ने आरोपी रामअवतार गेंडरे के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के तहत मामला दर्ज किया। मौके से एक पिकअप वाहन (क्रमांक सीजी 04 क्यूडी 6455), छह बड़े स्पीकर बॉक्स, एम्प्लीफायर मशीन, आठ हॉर्न, तीन डिस्को लाइट और एक जनरेटर जब्त किया गया। जब्त की गई सामग्री को थाने में सुरक्षित रखा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि इस घटना से दो दिन पहले भी कोतवाली पुलिस ने महामाया लॉन (भैरोंगंज) और प्रकाश नगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित डीजे पर कार्रवाई की थी। पुलिस ने डीजे संचालकों और आयोजकों को कड़ी चेतावनी दी है। बिना अनुमति और निर्धारित समय सीमा के बाद तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीमा समझकर लगाया अंगूठा, केसीसी का लाखों का कर्ज चढ़ा

बीमा के नाम पर केसीसी बनाकर आदिवासी महिलाओं के खातों से हुईं लाखों की निकासी

बैतूल | संवाददाता
rashtrabaan.in

जनसुनवाई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अनपढ़ आदिवासी महिलाओं को बीमा की बात कहकर अंगूठा लगवाया गया और उनके नाम से केसीसी बना दी गई। महिलाओं को लगा कि बीमा की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उनके खातों से 2 लाख 67 हजार 466 रुपये और 69 हजार 472 रुपये की राशि निकाल ली गई। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी और सीधे लाखों का कर्ज उनके नाम चढ़ा दिया गया। जब घर पर वसूली नोटिस पहुंचे तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।

विकासखण्ड भैसदेही अंतर्गत ग्राम गदराझिरी की आदिवासी महिलाएं छतुरा और सुकु ने जनसुनवाई में इसकी शिकायत कर कलेक्टर और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गदराझिरी निवासी आवेदिका छतुरा ने बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को आ.जा. वृहता सहकारी समिति मर्या से 2,67,466 रुपये जमा करने का नोटिस मिला। जब उन्होंने बैंक में जानकारी ली तो बताया गया कि केसीसी का पैसा बकाया है। स्टेटमेंट निकलवाने पर उनके खाते से टी.आर. शिवहरे (सागर) के नाम से राशि निकाले जाने की जानकारी सामने आई। छतुरा का कहना है कि वह अनपढ़ हैं, उन्हें केसीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुकेश आर्य निवासी गदराझिरी ने बीमा कराने के नाम पर कागज लिए और अंगूठा लगवाया। आरोप है कि टी.आर. सिवहरे द्वारा उनके खाते से राशि आहरित कर ली गई।

दूसरी आवेदिका सुकू आत्मज गेंदलाल ने बताया उन्हें भी दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को आ0जा0 वृहता सहकारी समिति मर्या से 69,472 रुपये जमा करने का नोटिस प्राप्त हुआ।

फाइनेंस कंपनी अधिकारियों पर धोखाधड़ी का आरोप

लोन वसूली के दौरान अवैध वसूली, कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

सिवनी में एक निजी फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों पर लोन वसूली के दौरान अवैध वसूली, धोखाधड़ी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित हितग्राहियों ने मंगलवार, 24 फरवरी को दोपहर करीब 4 बजे कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की सिवनी शाखा से कई हितग्राहियों ने मॉर्टगेज के आधार पर लोन लिया था।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि लोन स्वीकृति के समय उनसे मॉर्टगेज के नाम पर हजारों रुपये की अतिरिक्त वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, उन्हें पांच वर्ष की अवधि बताकर लोन दिया गया था, लेकिन पूरी राशि जमा करने के बाद लोन अवधि सात वर्ष दर्शा दी गई।

शिकायतकर्ताओं में अहिल्या ठाकरे, वसुंधरा सोनवाने, किरण पटले (ग्राम साल्हेखुर्द, बरघाट), मोहम्मद सलीम खान, आसिया बेगम (ग्राम बंडोल) और लोकेश जैन (गांधी वार्ड, सिवनी) शामिल हैं। सभी ने संयुक्त रूप से कंपनी के शाखा प्रबंधक प्रकाश तिवारी और क्षेत्रीय प्रबंधक लेखराम लाडिया पर अनुचित दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

आवेदकों का कहना है कि जब उन्होंने अतिरिक्त वसूली और लोन अवधि बढ़ाने पर आपत्ति जताई, तो अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज की और धमकी दी। आरोप है कि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, अधिकारियों द्वारा यह भी कहा गया कि उनकी 'ऊपर तक पहुंच' है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

पीड़ितों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली से आम लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि कुछ लोगों ने फाइनेंस कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों की शिकायत की है, तथ्यों की जांच के बाद विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कप्यूटर वर्ल्ड
सेल्स एंड सर्विस
लैपटॉप, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी कैमरा, होम थियेटर, प्रिंटर, लेमिनेशन, फोटो कॉपियर, नेटवर्किंग, प्रोजेक्टर, कॉर्टरेज रिफलिंग

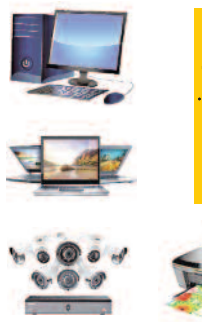

संपूर्ण कम्प्यूटर ऐससरीज उपलब्ध
पुराने कम्प्यूटर व लैपटॉप उपलब्ध

संपर्क- बैनगंगा कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, सिवनी, मो.न.-9302833332

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक संजय बघेल द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एमपी नगर भोपाल म.प्र से मुद्रित कराकर शिवनगर कॉलोनी सड़क मोहल्ला मरझोर जिला सिवनी से प्रकाशित।
RNI NO.: MPHIN/2015/72804 , **संपादक*** **संजय बघेल** पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र सिवनी होगा। E-mail: rashtrabaan@gmail.com. mob: 7000427433